PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 036
दि. 05.06.2026, शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

विश्व योग दिवस से पहले आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप अपने साथ स्वास्थ्य और कल्याण की दोहरी सौगात लेकर आई है : प्रधानमंत्री

योग मानवता को भारत का शाश्वत उपहार है! मन, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में जोड़ते हुए यह एक अधिक स्वस्थ, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विश्व की प्रेरणा देता है : प्रधानमंत्री

अहमदाबाद यूनेस्को की विश्व धरोहर नगरी है, और भारत के इस ऐतिहासिक शहर में इस आयोजन का होना पूरे देश के लिए गर्व का विषय है : प्रधानमंत्री

विश्व योग दिवस से पहले आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप अपने साथ स्वास्थ्य और कल्याण की दोहरी सौगात लेकर आई है : प्रधानमंत्री

इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में नई पहचान मिलेगी, और मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन को ओलंपिक तथा अन्य बहु-खेल आयोजनों में भी शामिल किया जाएगा : प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अहमदाबाद से वीडियो संदेश के माध्यम से प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया, जो वैश्विक खेल विरासत में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान है। श्री मोदी ने कहा, 'आज अहमदाबाद की धरती से विश्व की खेल विरासत में एक नया अध्याय जुड़ रहा है।'

इस अग्रणी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए विश्वभर से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी अहमदाबाद द्वारा किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा, 'अहमदाबाद यूनेस्को की विश्व धरोहर नगरी है, और भारत के इस ऐतिहासिक शहर में इस आयोजन का होना पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।'

विश्व स्तर पर आयोजित हो रहे योग उत्सवों के समागम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस विभिन्न देशों में अनेक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा, जबकि इसका मुख्य कार्यक्रम भारत के एक अन्य ऐतिहासिक शहर कोलकाता में आयोजित होगा। श्री मोदी ने कहा, 'विश्व योग दिवस से पहले आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप अपने साथ स्वास्थ्य और कल्याण की दोहरी सौगात लेकर आई है।'

योग को वैश्विक पहचान दिलाने की भारत की यात्रा का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि लगभग एक दशक पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन परंपरा को समस्त मानवता के स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण से जोड़ना था। श्री मोदी ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र में 190 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।'

योग की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में लाखों लोगों ने योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दैनिक दिनचर्या और जीवनशैली का हिस्सा बना लिया है। जीवंत परंपराओं के निरंतर विकासशील स्वरूप पर बल देते हुए उन्होंने विश्व योगासन चैंपियनशिप को योग के एक नए और समकालीन रूप में प्रासंगिक परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश का प्रतीक बताया।

योगासन को एक मान्यता प्राप्त प्रतिस्पर्धी खेल विधा के रूप में स्थापित करने में इस चैंपियनशिप के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में इसे विश्व के प्रमुख खेल आयोजनों में स्थान मिलेगा। श्री मोदी ने कहा, 'इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में नई पहचान मिलेगी, और मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन को ओलंपिक तथा अन्य बहु-खेल आयोजनों में भी शामिल किया जाएगा।'

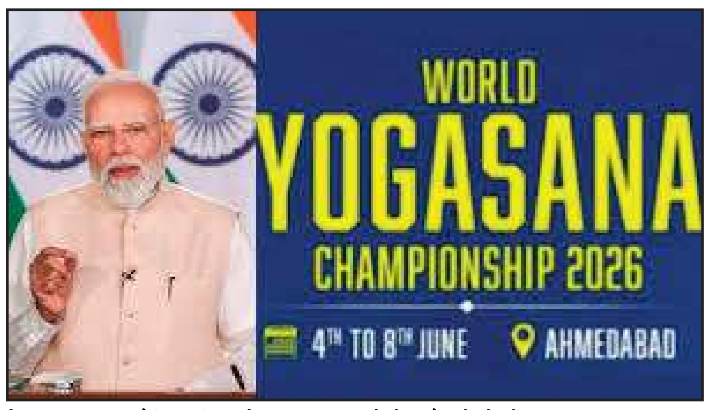

अहमदाबाद की अग्रणी भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल जगत में मुख्यधारा की पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक खेल के रूप में योग के विकास के व्यापक आर्थिक और व्यावसायिक प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न क्षेत्रों और पेशों में नए अवसर उत्पन्न होंगे। श्री मोदी ने कहा, 'जैसे-जैसे योगासन खेल का विस्तार होगा, वैसे-वैसे नई संभावनाएँ भी विकसित होंगी, जिससे खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, शोधकताओं और आयोजन प्रबंधकों के लिए नए करियर अवसर सृजित होंगे।'

इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने समकालीन वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं और दीघार्यु की आकांक्षा रखने वाली आधुनिक आबादी के लिए योग की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा, 'जो लोग लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय बने रहने के उपाय खोज रहे हैं, उनके लिए योग एक अत्यंत उपयुक्त विकल्प है।'

योग को एक ओर मुक्त कर देने वाली साधना और दूसरी ओर किफायती स्वास्थ्य समाधान बताते हुए श्री मोदी ने इसके सार्वभौमिक रूप से सुलभ होने का समग्र संदेश दिया। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक स्मरणीय मंत्र प्रस्तुत करते हुए उन्होंने योग की रोग-निवारक क्षमता को सरल शब्दों में व्यक्त किया।

किसान भाई-बहनों की आय बढ़ाने के साथ कृषि के समग्र विकास का रोडमैप- श्री शिवराज सिंह

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मध्य प्रदेश के रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास जिलों के लिए तैयार विशेष कृषि रोडमैप अब देश में कृषि परिवर्तन के एक मॉडल के रूप में उभरने जा रहा है। रायसेन में आयोजित "उन्नत कृषि महोत्सव" के दौरान की गई घोषणा को आगे बढ़ाते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसान की आय, जल संरक्षण, मिट्टी की सेहत, वैज्ञानिक खेती और योजनाओं के प्रभावी अभिसरण पर आधारित एक जवाबदेह मिशन है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के कृषि रोडमैप के लिए आज दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक ली जिसमें मध्य

प्रदेश के कृषि मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की।

रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास जिलों को कृषि विकास का आदर्श मॉडल बनाने की दिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा विजन सामने रखा है। उन्होंने आज की महत्वपूर्ण बैठक में कहा कि इन चार जिलों में जो कृषि रोडमैप लागू किया जा रहा है, वह केवल समीक्षा का दस्तावेज नहीं, बल्कि खेत, किसान और भविष्य की खेती को केंद्र में रखकर बनाया गया परिवर्तन का ठोस खाका है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने स्वयं इन क्षेत्रों के खेतों की स्थिति देखी है। भूजल स्तर में गिरावट, मिट्टी की कमजोर होती सेहत और किसान की मेहनत के अनुरूप आय न मिलना चिंता का विषय है। इसी कारण उनकी दिली इच्छा है कि देवास, सीहोर, रायसेन और विदिशा कृषि सुधार के ऐसे सफल मॉडल बनें।

लखनऊ बना देश का नंबर-1 सोलर जिला, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी ने रचा इतिहास, कई श्रेणियों में मिला पहला स्थान

देशभर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश ने "टॉप थ्री स्टेट इंस्टॉलेशन" श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है.

(जीएनएस)।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश ने नई दिल्ली में आयोजित "पीएम सूर्य घर पुरस्कार समारोह" में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देशभर में परचम लहराया है. यूपी को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान मिला, जिससे स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में उसकी अग्रणी भूमिका और मजबूत हुई है.

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत देशभर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश ने "टॉप थ्री स्टेट इंस्टॉलेशन" श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया. इस श्रेणी में गुजरात पहले स्थान पर रहा. उत्तर प्रदेश की यह उपलब्धि राज्य में सौर ऊर्जा के प्रति

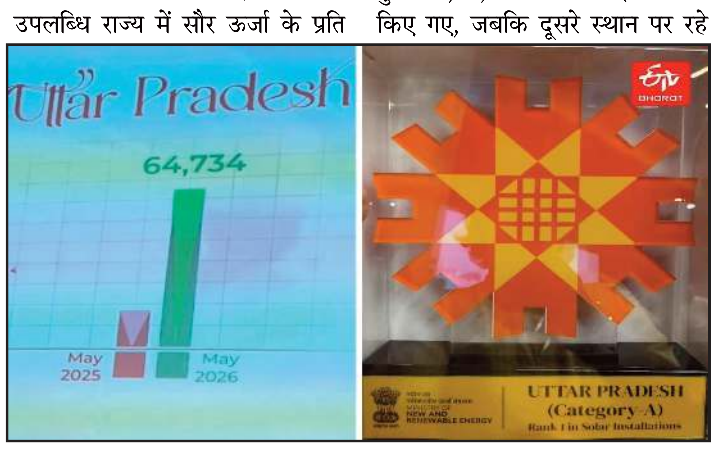

बढ़ती जागरूकता एवं प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण है.

जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया. लखनऊ में कुल 1,02,596 सोलर इंस्टॉलेशन किए गए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे नागपुर में 89,255 इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए. यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के तेजी से विस्तार को दशार्ती है.

राज्यवार "वेरी हाई कंज्यूमर बेस" श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ. इसके साथ ही सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, सर्वाधिक सोलर इंस्टॉलेशन और अधिकतम वेंडर रजिस्ट्रेशन जैसी महत्वपूर्ण श्रेणियों में भी उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया.

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने इन उपलब्धियों का श्रेय पीएम और सीएम को दिया. कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी. सौर ऊर्जा न सिर्फ प्रदूषण मुक्त बिजली उपलब्ध कराती है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सौर ऊर्जा क्रांति का अग्रदूत बनकर उभरा है.

यूपी में 206 पीपीएस अफसरों का तबादला, लखनऊ में तैनात अफसर भी बदले, तीन पीसीएस के भी ट्रांसफर

(जीएनएस)।

लखनऊ, डीजीपी मुख्यालय ने बृहस्पतिवार को डिप्टी एसपी रैंक के 206 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। लखनऊ में तैनात करीब एक दर्जन डिप्टी एसपी को भी बदला गया है। वहीं, तीन पीसीएस अफसरों के भी तबादले कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जितेंद्र कुमार को शाहजहांपुर भेजा गया है। लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात विकास कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री सुरक्षा भेजा गया है। गोरखपुर में तैनात उदय प्रताप सिंह द्वितीय को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त बनाया गया है। लखनऊ में तैनात सतीश कुमार राय को मेरठ में पीएसी की छठवीं वाहिनी भेजा गया है।

इसी तरह राजधानी में सहायक

पुलिस आयुक्त अभय कुमार मल्ल को बलरामपुर भेजा गया है। महोबा में तैनात गौरव उपाध्याय और अंबेडकरनगर में तैनात शुभम कुमार को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुरक्षा से वाराणसी कमिश्नरेट भेजे गए राजेश कुमार सिंह को अब लखनऊ कमिश्नरेट में तैनाती दी गई है।

ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की और हाल के दिनों में भारत-ब्रिटेन की साझेदारी के

अधिक प्रगाढ़ होने की सराहना की, जिससे दोनों देशों के लिए अभूतपूर्व विकास के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-ब्रिटेन विजन 2035 साझेदारी का मार्गदर्शन करता रहेगा और वैश्विक भलाई के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया: "ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर से मिलकर प्रसन्नता हुई। हाल के दिनों में भारत-ब्रिटेन साझेदारी घनिष्ठ होना सराहनीय है।

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति, सुश्री डेल्सी रोड्रिगेज ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात पर हर्ष जाहिर करते हुए कहा कि बैठक में ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी, कृषि, और स्वास्थ्य में सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों की अवामों के बीच संबंध मजबूत करने पर विस्तृत बातचीत हुई।

श्री मोदी ने कहा कि वेनेजुएला लैटिन अमेरिका में हमारा एक मूल्यवान साझेदार है और इस बात पर जोर दिया कि इस देश के साथ घनिष्ठ सहयोग 'विकासशील देशों' के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हुमायूंपुर होटल में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, टला बड़ा हादसा नहीं हुआ कोई बड़ा नुकसान

(जीएनएस)।

दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव के पास हुमायूंपुर इलाके में एक होटल में आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि राहत की बात ये रही कि समय रहते दमकल विभाग की तेजी से कार्रवाई की वजह से आग पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यह घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है।

कैसे लगी आग?

जानकारी के मुताबिक होटल के बेसमेंट में रखे फर्नीचर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही धुआं फैलने लगा, जिससे अफरा-तफरी मच गई। तुरंत ही होटल स्टाफ और आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर करीब 5 फायर टेंडर की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया और लगभग 15 मिनट में आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया।

कोई हताहत नहीं

दमकल अधिकारियों के अनुसार इस घटना में किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। समय पर कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया।

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब एक दिन पहले ही दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में होटल में भीषण आग लगी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में हुमायूंपुर की यह घटना एक बार फिर होटल और बिल्डिंगों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।

जांच जारी

फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शुरूआती तौर पर माना जा रहा है कि बेसमेंट में रखा सामान आग की चपेट में आया, लेकिन असली वजह रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी।

बंगाल में 'खेला'! 60 विधायकों की बगावत के बाद अब क्या 28 सांसद भी बदलेंगे पाला

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। पिछले 15 सालों तक बंगाल की सत्ता पर एकछत्र राज करने वाली ममता बनर्जी के पैर के नीचे से अचानक सियासी जमीन खिसक गई है। हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद अभी पार्टी संभल भी नहीं पाई थी कि 24 घंटे के भीतर वो सब कुछ हो गया जिसकी कल्पना खुद ममता दीदी ने भी नहीं की होगी।

जिस बागी विधायक को ममता बनर्जी ने तीन दिन पहले गुस्से में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, उसी नेता ने आधी से ज्यादा टीएमसी तोड़ दी। टीएमसी के 80 में से 60 विधायकों का समर्थन जुटाकर वह विधानसभा में 'नेता प्रतिपक्ष' की कुर्सी पर बैठ गया है। अब सबसे बड़ा डर यह है कि विधानसभा के बाद क्या ममता की 'टीम दिल्ली यानी उनके सांसदों में भी बड़ी टूट होने वाली है? आइए इस पूरे सियासी बवंडर का आसान भाषा में पोस्टमार्टम करते हैं।

सरमा कैबिनेट का आज होगा विस्तार, ये 12 दिग्गज नेता लेंगे मंत्री पद की शपथ

(जीएनएस)।

असम की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी कैबिनेट के विस्तार का बड़ा ऐलान कर दिया है। हाल ही में आए राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, आज यानी 5 जून को दोपहर 12:45 बजे 12 नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्य में 'ठऊ्र 3.0' युग की शुरूआत के साथ ही इस नए मंत्रिमंडल से जनता को काफी उम्मीदें हैं।

मुख्यमंत्री सरमा की इस नई टीम में अनुभवी और जमीनी पकड़ रखने वाले 12 प्रमुख चेहरों को जगह दी गई है। राजभवन में होने वाले इस समारोह में जो नेता आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। अश्विनी राय सरकार अशोक सिंघल, बिमल बोरा और बिस्वजीत दैमारी, जयंत मल्लाबरुआ और कौशिक राय, केशव महंत और कृष्णेंदु पॉल, नीलिमा देवी और पीयूष हजारिका, रनोज पेगु और सुशांत

बोरगोहेन

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीते 12 मई को ही खानपारा वेटरनरी कॉलेज मैदान में एक भव्य समारोह के दौरान अपने दूसरे कार्यकाल की शुरूआत की थी। इस बार के चुनावों में बीजेपी (इखढ) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 126 सीटों में से कुल 102 सीटों पर बंपर जीत हासिल की है।

कैबिनेट की इस नई लिस्ट से पहले भी कुछ सीनियर नेता पहले ही मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जो पहले से ही काउंसिल के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। इनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

कार्यकाल संभालने के बाद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। अपनी इस पहली शिष्टाचार मुलाकात के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को असम की तेज आर्थिक तरक्की और भविष्य के डेवलपमेंट प्लान्स की जानकारी दी।

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर चर्चा हेतु अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का 1 से 4 जून 2026 तक दिल्ली दौरा

भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी 2026 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें पारस्परिक एवं परस्पर

लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के लिए रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की गई। इस रूपरेखा ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर व्यापक वाताओं के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

लखनऊ में सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौके पर हो गई मौत

(जीएनएस)।

लखनऊ। विकासनगर सेक्टर सी में बुधवार देर रात सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर 52 वर्षीय संदीप सिंह ने शराब के नशे में खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर परिवारजन व पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो जमीन पर पड़े हुए थे।

उन्हें उठाकर ट्रामा सेंटर ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर विकासनगर आलोक सिंह ने बताया कि लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त कर ली गई है।आत्महत्या का कारण पता लगाया जा रहा है।

इंस्पेक्टर ने बताया कि सेक्टर सी के सबोली में संदीप सिंह पत्नी व दो बेटियों के साथ रहते थे। निजी कंपनी में सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइजर थे।

मृतक के भाई ने बताया कि संदीप बहुत ज्यादा शराब पीने के लती थे। बुधवार की रात करीब दस बजे नशे की हालत में घर पहुंचे और अपने कमरे में चले गए। उन्होंने किसी से बात तक नहीं की। कुछ देर बाद संदीप के कमरे से आवाज आई तो देखा कि उन्होंने कनपटी में लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली।

लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े हैं। यह देख चीखपुकार मच गई। पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। परिवारजन ने पड़ोसियों की मदद से ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस को सूचना दी।

इंस्पेक्टर ने बताया कि धटना स्थल पर पहुंच कर फारेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। साथ ही लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त कर जांच के लिए भेज दिया गया है।

परिवारजन से गोली मारने के कारण पूछा गया तो कोई उचित जवाब नहीं मिला। इस पर उनकी कंपनी के लोगों से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल परिवारजन की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में 300 करोड़ रुपये का जमीन घोटाला, ईडी ने शुरू की जांच, LDA से मांगी फाइल

(जीएनएस)।

लखनऊ : गोमती नगर विस्तार इलाके में हुए करीब 300 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुरू कर दी है. ईडी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अर्जन विभाग से इस घोटाले से जुड़ी सभी फाइलें और दस्तावेज तलब किए हैं. इसके बाद एलडीए दफ्तर में हिमालय सहकारी समिति से जुड़े दस्तावेज तलाशे जा रहे हैं. अधिकारी रिकॉर्ड जुटाने में लगे हैं.

मामला गोमती नगर विस्तार इलाके में समिति के नाम पर जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. आरोप है कि कुछ जमीन दलालों और उनके कारिंदों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया. दिवंगत भूमिया दिलीप सिंह बाफला से जुड़ा यह मामला है. जमीनों की हेराफेरी कर अवैध तरीके से लाखों रुपये कमाए गए. इन जमीनों की असली कीमत को छिपाकर कम दाम पर रजिस्ट्री कराई गई और बाद में ऊंचे दाम पर बेच दिया गया.

रसूखदारों को दी गई जमीन : जिन लोगों को यह जमीन पात्रता के आधार पर दी जानी चाहिए थी उन्हें न देखकर रसूखदारों को दी गई. ईडी को

शिकायत मिली थी कि इस घोटाले में करोड़ों रुपये का काला धन लगाया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करने के लिए ईडी ने अब सीधे एलडीए से दस्तावेज मांगे हैं. मांगी गई फाइलों में जमीन अधिग्रहण से जुड़े कागजात, रजिस्ट्री की कॉपी, आवंटन पत्र और समितियों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं.

फाइल जुटा रहे : एलडीए के अर्जन विभाग के अधिकारी इन फाइलों को इकट्ठा कर रहे हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि जैसे ही ईडी को सभी दस्तावेज मिल जाएंगे, उनकी जांच शुरू हो जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में जरूरी कागजात मांगे. हिमालय सहकारी समिति से जुड़े सभी दस्तावेज हम परिवर्तन निदेशालय के हवाले कर देंगे. हमारा इस पूरे मामले में यही रोल है.

दिलीप सिंह बाफिला की हिमालयन (द हिमालयन) सहकारी आवास समिति में मुख्य रूप से गोमतीनगर और गोमतीनगर विस्तार के जमीन समायोजन/आवंटन घोटाला शामिल है.

घोटाले की मुख्य बातें : द हिमालयन सहकारी आवास समिति और बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति उनके भतीजे प्रवीण सिंह बाफिला से जुड़ी है. इसके माध्यम से 234 भूखंडों (हिमालयन में करीब 122 और दूसरी में 112) का अनियमित फर्जी समायोजन किया गया. छऊ्अ की अधिग्रहित जमीन के बदले समायोजन के नाम पर फर्जी सदस्य परिवार, रिश्तेदार आदि, बनाकर प्राइम लोकेशन के बड़े प्लॉट कम कीमत पर आवंटित किए गए. तय सीमा से ज्यादा जमीन दी गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.

मध्य प्रदेश से तरुण चुग, राजस्थान से अलका गुर्जर, भाजपा की लिस्ट में 11 नेता कौन? इन नामों ने बढ़ाई हलचल

(जीएनएस)।

भारतीय जनता पार्टी (इखढ) ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ओडिशा से कुल 11 नामों का ऐलान किया है। इस सूची में कई अनुभवी संगठनात्मक चेहरों को मौका मिला है, वहीं कुछ फैसलों ने राजनीतिक गलियारों में नई चचाओं को भी जन्म दे दिया है।

बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अहम राज्यों में बड़े चेहरों पर दांव लगाया है। मध्य प्रदेश से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया है, जो संगठन में लंबे समय से मजबूत पकड़ रखते हैं। उनके साथ ही एमपी से रजनीश अग्रवाल को भी संसद के उच्च सदन का टिकट दिया गया है।

बात अगर राजस्थान की करें तो यहां का समीकरण सबसे दिलचस्प रहा। काफी समय से चर्चा थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अलका गुर्जर और राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान से इस बार केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा टिकट नहीं मिला है, जिनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है।

इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नाम ओडिशा से

सामने आया है। बीजेपी ने ओडिशा राज्यसभा उप-चुनाव के लिए देबाशीष सामंतराय को अपना उम्मीदवार बनाया है।

सामंतराय ने हाल ही में 25 मई को बीजू जनता दल (BJD) से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने उन्हें तुरंत राज्यसभा का टिकट देकर न सिर्फ पुरस्कृत किया है, बल्कि ओडिशा में अपने पैर और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

पूर्वोत्तर पर भी फोकस

भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक और मणिपुर से ए. शारदा देवी को उम्मीदवार बनाया है। शारदा देवी का नाम खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि वह भाजपा की महिला नेतृत्व वाली प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। इन नामों के जरिए पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत करने का संकेत दिया है।

कब होगा मतदान और क्या है संसद का मौजूदा गणित?

चुनाव का पूरा शेड्यूलः राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। इसके बाद 9 जून को पर्चों की जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सभी सीटों पर 18 जून को सुबह से मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। 10 राज्यों की 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होने हैं, जबकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र की एक-एक सीट पर उप-चुनाव होगा।

संख्या बल में कौन कितना मजबूतः वर्तमान में 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अकेले बीजेपी के 113 सदस्य हैं, जबकि एनडीए (NDA) का कुल आंकड़ा 148 तक पहुंच चुका है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां बीजेपी के पास बहुमत का अच्छा आंकड़ा है, जिससे इन सभी उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जून के महीने में मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह जैसे कई दिग्गज नेता रिटायर हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी उच्च सदन में अपनी ताकत और बढ़ाना चाहती है।

BJP ने क्या संदेश देने की कोशिश की?

भाजपा की इस सूची को देखें तो साफ नजर आता है कि पार्टी ने संगठन के पुराने और भरोसेमंद नेताओं को प्राथमिकता दी है। साथ ही महिला नेतृत्व और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी महत्व दिया गया है।

तरुण चुग, अलका गुर्जर, सतीश पूनिया और ए. शारदा देवी जैसे नाम यह संकेत देते हैं कि भाजपा केवल चुनावी समीकरण नहीं, बल्कि संगठनात्मक निष्ठा को भी पुरस्कृत करने की रणनीति पर काम कर रही है। अब 18 जून को होने वाले चुनाव के बाद यह साफ होगा कि राज्यसभा में भाजपा और एनडीए की ताकत कितनी और बढ़ती है।

बंगाल में पूर्व मंत्री के भाई स्वरूप बिश्वास गिरफ्तार, क्या लगे हैं आरोप?

(जीएनएस)।

बंगाल से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री अरूप बिश्वास के भाई और टीएमसी नेता स्वरूप बिश्वास को न्यू अलीपुर पुलिस ने बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। स्वरूप बिश्वास पर जबरन वसूली और छेड़छाड़ जैसे कई बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से पूरी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस को पिछले कुछ समय से कोलकाता के लोकल स्टूडियो इलाकों से स्वरूप बिश्वास के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। पीड़ितों का आरोप है कि स्वरूप

बिश्वास काफी समय से टॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को डरा-धमका रहे थे और उनसे मोटी रकम वसूल रहे थे। बात सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं रही, उन पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का भी संगीन आरोप लगा है।

पूर्व मंत्री के भाई होने से गर्माई राजनीति

स्वरूप बिश्वास की गिरफ्तारी की पुष्टि खुद पुलिस के आला अधिकारियों ने की है। चूंकि वह पूर्व मंत्री अरूप बिश्वास के सगे भाई हैं, इसलिए इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पश्चिम बंगाल के सियासी हलकों में इस गिरफ्तारी को लेकर लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है और विरोधी दल भी सरकार को घेरने की तैयारी में हैं।

पुलिस स्टेशन में मैराथन पूछताछ जारी

बुधवार देर रात हुई इस अचानक कार्रवाई के बाद पुलिस स्वरूप बिश्वास को थाने ले आई है। फिलहाल, न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन में सीनियर अफसरों की मौजूदगी में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी शुरूआती दौर में है और जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, इस रैकेट से जुड़े कई और बड़े चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं।

टीजीटी परीक्षा 2026; लखनऊ में पांच 'मुन्ना भाई' गिरफ्तार, दूसरे अभ्यर्थी की जगह दे रहे थे एग्जाम

आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, मोबाइल, नकदी सहित कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं.

(जीएनएस)।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा (टीजीटी परीक्षा 2026) में फर्जी अभ्यर्थी बनकर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले 'मुन्ना भाई' को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, मोबाइल, नकदी सहित कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं. सभी गिरफ्तार आरोपियों के बारे में लखनऊ पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी है.

पुलिस मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, हुसैनगंज स्थित बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में जौनपुर निवासी राजेश प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि आरोपी अभ्यर्थी विजय प्रताप सिंह की जगह पर परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में पता चला है कि यह आरोपी फर्जी आधार कार्ड और अन्य कूटरचित दस्तावेजों की मदद से परीक्षा केंद्र में प्रवेश पा गया था.

आरोपी के पास से आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, ब्लैंक चेक व एक कार बरामद हुई है.

महानगर स्थित आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन के दौरान पुलिस ने आजमगढ़ निवासी मन्तेश सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि यह प्रयागराज निवासी अमरजीत सिंह के स्थान पर परीक्षा देने आया था. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में यह बात निकल के सामने आई है कि उसने पांच लाख रुपये के बदले सॉल्वर बनकर परीक्षा पास कराने का ठेका लिया था. इस काम के लिए इसे पांच हजार रुपये एडवांस मिले थे. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र की प्रति, मोबाइल फोन व कैश बरामद किया है.

नाका हिंडोला स्थिति डीएवी डिग्री कॉलेज में प्रयागराज निवासी रंगबहादुर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह अभ्यर्थी अवध राज यादव के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है. रंगबहादुर को फर्जी आधार कार्ड और प्रवेश पत्र के सहारे परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया है. आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने अभ्यर्थी अवध राज यादव को भी गिरफ्तार किया है. दोनों के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

अमीनाबाद के विद्यांत हिंदू इंटर कॉलेज से राम मनुज नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह फरुर्खाबाद निवासी अभ्यर्थी जितेंद्र सिंह यादव की जगह पर परीक्षा देने पहुंचा था. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन के दौरान उसकी मुलाकात पंकज नामक हुई थी. पंकज यादव ने ही उसे फर्जी दस्तावेज दिए थे और पेपर सॉल्व करने के लिए तैयार किया था.

यूपी में बहुमंजिला इमारतों और होटलों में फायर सेफ्टी की होगी जांच, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊ। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्तरां में लगी भीषण आग की घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की बहुमंजिली इमारतों, होटलों, कार्यालयों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निसुरक्षा की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही शुक्रवार को होने वाली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में अग्निशमन सुरक्षा की तैयारियों पर मंथन करेंगे।

दिल्ली अग्निकांड में मृतकों के स्वजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद मुख्यमंत्री ने बहुमंजिली इमारतों में अग्निसुरक्षा की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके बाद अग्निसुरक्षा विभाग ने गुरुवार को विभिन्न इमारतों का दौरा कर मौके पर आग से सुरक्षा

को लेकर किए गए उपायों की जांच की।

शुक्रवार को होने वाली बैठक में विकास प्राधिकरणों, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग समेत संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अग्निसुरक्षा को लेकर कार्ययोजना के साथ बैठक में शामिल हों।

यह वीडियो भी देखें

वहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी बहुमंजिली इमारतों, कार्यालयों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर वहां मौजूद फायर सेफ्टी सिस्टम को और मजबूत बनाने के निर्देश अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिए हैं कि अग्निसुरक्षा को लेकर तैयार विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जिन संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अग्निशमन विभाग ने राज्य के होटलों की जांच शुरू कर दी है।

सीबीएसई ने कैसे नाकाम किया साइबर हमला? डीओएस अटैक के बीच चलता रहा री-इवैल्यूएशन पोर्टल, बोर्ड ने कहा-डेटा सुरक्षित

(जीएनएस)।

सीबीएसई बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बोर्ड के री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल को हाल ही में साइबर हमले का निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन तकनीकी टीम ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। इस वजह से पोर्टल की सेवाओं पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा और छात्रों का काम लगातार चलता रहा।

बोर्ड के अनुसार हजारों छात्रों ने बिना किसी रुकावट के अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा किए। बढ़ते ऑनलाइन खतरों के बीच यह घटना बताती है कि परीक्षा से जुड़ी डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। उइरए ने भी साफ किया है कि छात्रों का डेटा सुरक्षित है और पोर्टल पूरी तरह सामान्य तरीके से काम कर रहा है।

पोर्टल पर किया गया साइबर हमला

उइरए ने बताया कि उसके री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) साइबर अटैक करने

की कोशिश की गई। ऐसे हमलों में किसी वेबसाइट या सर्वर पर बहुत बड़ी मात्रा में डेटा भेजा जाता है ताकि उसकी गति धीमी हो जाए या वह काम करना बंद कर दे। बोर्ड के अनुसार पोर्टल पर करीब 3.8 मिलियन डेटा पैकेट भेजे गए थे। हालांकि तकनीकी टीम लगातार सिस्टम पर नजर रखे हुए थी। संदिग्ध गतिविधि सामने आते ही सुरक्षा उपाय लागू किए गए और हमले को सफल होने से पहले ही रोक दिया गया।

छात्रों के आवेदन जारी रहे

साइबर हमले के बावजूद पोर्टल पर छात्रों की गतिविधियां सामान्य बनी रहीं। बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार रात तक 56 हजार से अधिक आवेदन वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए प्राप्त हो चुके थे। यह संख्या बताती है कि बड़ी संख्या में छात्र अपने परीक्षा परिणामों की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं। कई छात्र अंकों की पुनर्गणना के लिए आवेदन कर रहे हैं, जबकि कुछ छात्रों ने उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है।

किन मामलों में दर्ज कर सकते हैं शिकायत

CBSE पहले ही छात्रों को उनकी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करा चुका है। इन कॉपियों को देखने के बाद छात्र अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाते हैं तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि उत्तर पुस्तिका का कोई पेज गायब हो, अतिरिक्त शीट शामिल न की गई हो, स्कैन कॉपी साफ दिखाई न दे रही हो या गलत प्रश्नपत्र सेट के आधार पर मूल्यांकन किया गया हो, तो छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी खास उत्तर के पुनर्मूल्यांकन की मांग भी की जा सकती है।

सिस्टम को और मजबूत बना रहा बोर्ड

बोर्ड का कहना है कि तकनीकी टीम लगातार पोर्टल की निगरानी कर रही है। आवेदन की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है ताकि छात्रों को किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े। उइरए ने बताया कि कुछ समय पहले पोर्टल को तकनीकी अपग्रेड के लिए अस्थायी रूप से रोका गया था। इसके बाद सुरक्षा और प्रदर्शन दोनों को बेहतर बनाया गया, जिससे सेवाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित और तेज हो सकें।

भुगतान के लिए कई विकल्प उपलब्ध

आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उइरए ने कई सरकारी बैंकों के पेमेंट गेटवे को अपने सिस्टम से जोड़ा है।

मुंबईकर हो जाएं अलर्ट! मानसून में समुद्र दिखाएगा रौद्र रूप, बीएमसी ने जारी किया हाई टाइड अलर्ट

(जीएनएस)।

मुंबई में रहने वालों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। शहर में मानसून के साथ समुद्र का मिजाज भी काफी खतरनाक होने वाला है। मॉनसून में मुंबई में समुद्र एक नहीं कई बार रौद्र रूप धारण करने वाला है। समुद्र से जानलेवा ऊंची समुद्री लहरें उठेगीं।

गुरुवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जून से सितंबर के बीच 24 बार 4.5 मीटर से ज्यादा ऊंची हाई टाइड आएगी। ऐसे में मुंबईकरों को समुद्र किनारे जाने से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है।

16 जुलाई को सबसे बड़ा खतरा

इटउ के अनुसार, इस मानसून का सबसे खतरनाक हाई टाइड 16 जुलाई को आने की संभावना है। उस दिन समुद्री लहरें करीब 4.89 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं। इसे देखते हुए

प्रशासन ने लोगों को समुद्र तट और तटीय इलाकों से दूर रहने की सख्त सलाह दी है। पहली हाई टाइड की शुरूआत 14 जून से 19 जून के बीच होने वाली है।

चार महीनों में 24 बार हाई टाइड का अलर्ट

मानसून के दौरान जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में कई बार समुद्र उफान पर रहेगा। BMC के आंकड़ों के मुताबिक जून में 6, जुलाई में 6, अगस्त में 5 और सितंबर में 7 बार 4.5 मीटर से अधिक ऊंची हाई टाइड दर्ज की जाएगी।

समुद्र किनारे सेल्फी और सैर से बचें

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि हाई टाइड के दौरान समुद्र किनारे घूमने, सेल्फी लेने या पानी के करीब जाने की गलती न करें। तेज हवाएं और ऊंची लहरें हादसों का कारण बन सकती हैं। वहीं मछुआरों को भी विशेष सतर्कता बरतने और मौसम संबंधी सभी चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

भय पैदाकर वोटरों को लुभाते दल

कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया है कि मोदी सरकार मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर घबराईं हुईं है और अपने तंत्र के भीतर से ही घिर चुकी है। पाटी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि असली समस्या यह है कि देश में निजी कम्पनियों का निवेश बेहद कम है जबकि कम्पनियों की कमाई रिकार्ड ऊंचाई पर है। उनका आकलन है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी वंपनियों के निवेश की दर में बहुत गिरावट आई है। मजे की बात तो यह है कि कांग्रेस के यह अर्थशास्त्री नेता इतना भयानक माहौल इस आधार पर बना रहे हैं कि एक मीडिया चैनल ने दावा किया है कि केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी करने की योजना बना रही है जिसके तहत विदेशी निवेशकों यानि एफडीआई द्वारा भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश पर लगने वाले 17.5 प्रतिशत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।

दरअसल कांग्रेसी अर्थशास्त्री जयराम रमेश ने अपनी डर बेचने की दुकान को चमकाने के लिए एक मीडिया टीवी चैनल की रिपोर्ट को आधार बना तो लिया किन्तु उन्होंने ऐसा कोई तार्किक आधार नहीं दिया जिससे कि उनकी बातों पर भरोसा किया जा सके। आयकर अधिनियम में बदलाव की बात कहां से आ गई? समझ से बाहर की बात तो यह है कि एक केन्द्रीय मंत्री रह चुके व्यक्ति को या तो सूचना का कोई ठोस आधार देना होता है या फिर विमर्श स्थापित करने के लिए वुछ ऐसे तर्क देने पड़ते हैं जो भले ही गलत हों किन्तु वे लगें बिल्वुल सच।

वास्तविकता तो यह है कि जयराम की पाटी बिल्वुल वामपंथी अवतार में है। इसलिए वह ऐसा दावा करने से पहले कि सरकार पूंजीगत लाभ कर को समाप्त करने जा रही है, यह नहीं सोचा कि कोई भी सरकार इस वक्त ऐसा वुछ भी करने का खतरा नहीं ले सकती जिससे राजकोषीय घाटा बढ़े। जयराम को इस बात से बहुत एतराज है कि देश की वंपनियां लाभ तो खूब कमा रही हैं किन्तु देश में पूंजी निवेश नहीं कर रही हैं। सच तो यह है कि जयराम रमेश जैसे वुछ अर्थशास्त्रियों ने डर का जो अपना शोरूम सजा रखा है उस पर भरोसा करने वालों की लगातार संख्या कम हो रही है। सांख्यकीय और तार्किक आधार दिए बिना आंय-बांय-सांय बोलने से कोई भारतीय अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का अनुमान नहीं लगा रहा है। जो बात जयराम रमेश जानते हुए भी छिपा रहे हैं वह यह है कि भारतीय कम्पनियां इस वक्त देश के रक्षा उत्पादन, ऊर्जा क्षेत्र, सड़क निर्माण, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट और बंदरगाह निर्माण में पूंजी निवेश नहीं बल्कि पूंजी झोंक रहे हैं। उक्त क्षेत्रों में सरकार कम और निजी वंपनियां ज्यादा पूंजी लगा रही हैं। यही कारण है कि वुछ ही दिनों में भारतीय निजी वंपनियां निर्माण के क्षेत्र में चीन, साउथ कोरिया, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी की वंपनियों से आगे निकल चुकी हैं। अब चूंकि पाटी की वामपंथी विचारधारा की एसओपी के तहत ही बोलना भी है और सरकार की आलोचना भी करनी है इसीलिए एक अर्थशास्त्री जयराम रमेश तथ्यों से खिलवाड़ कर रहे हैं जो मात्र राजनीतिक उद्देश्य के लिए अर्थशास्त्र के प्रति अनिभिज्ञता एवं अनिच्छा रखने वालों को बहकाया जा सके। सच यह है कि वुछ अंतर्राष्ट्रीय अस्थाई बाधाओं के कारण मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला किन्तु अर्थव्यवस्था कदापि कमजोर नहीं हुई है।

गोरखपुर लौट चुके थे योगी, तभी आया अमित शाह का फोन और बदल गया सब कुछ, सीएम बनने की वो कहानी

(जीएनएस)।

आज योगी आदित्यनाथ, वो नाम है, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को नई पहचान दी और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने पर पूरा जोर लगा दिया है। 'योगी नीति' का असर यह है कि उसका प्रभाव दूसरे राज्यों तक भी जाता है।

गोरखपुरः मंदिरों के परिसरों में गोरक्षपीठाधीश्वर का योग और मंदिर की दहलीज लांघते ही राजयोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी वो शख्सियत जिनके नाम से गुंडे-माफिया कांपते हैं, जिनकी नीति पूरे देश में हिट है और जिनका मॉडल हर राज्य अपनाना चाहता है। एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ अपने धर्म का कर्तव्यनिष्ठा से पालन करने वाले योगी आदित्यनाथ आज भारतीय राजनीति का वो नाम बन चुके हैं कि लोग उन्हें देश के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री कहते हैं।

5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव में जन्मे अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ आज कॉमरेड होते, अगर उनके जीजा की चली होती। योगी आदित्यनाथ का मन स्कूल के दौर से ही सियासत में लगना शुरू हो चुका था। वे एबीवीपी के सदस्य बने और छात्रसंघ चुनाव के दौरान सचिव पद के लिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी ठोकी, लेकिन टिकट नहीं मिला। अजय सिंह बिष्ट निर्दलीय मैदान में उतर पड़े। वे इस चुनाव में हार चुके थे। दिलचस्प यह था कि अजय सिंह बिष्ट की बहन के देवर यानी रिश्ते में जीजा लेफ्ट छात्र संगठन एसएफआई के सदस्य हुआ करते थे। वे चाहते थे कि युवा अजय एसएफआई ज्वाइन करे, लेकिन उसी दौरान अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात एबीवीपी कार्यकर्ता प्रमोद रावत से हुई। उन्हीं के कहने पर अजय सिंह बिष्ट ने एबीवीपी ज्वाइन कर ली।

विदेश जाने वाली टीम में योगी का नाम

2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। महीनों कड़ी मेहनत, प्रदेशभर के दौरे के बाद जब चुनाव प्रचार और वोटिंग खत्म हो चुकी थी, योगी आदित्यनाथ एक हफ्ते का ब्रेक लेना चाहते थे। उन्हें विदेश जाने का ऑफर भी मिल चुका था, क्योंकि वे उस समय एक सांसद थे। यह ऑफर उन्हें विदेश मंत्रालय की टीम ने दिया था, जो स्पेन जाने वाली थी। दिलचस्प यह था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस टीम के दौरे से योगी आदित्यनाथ का नाम निकाल दिया था। योगी आदित्यनाथ को शायद कुछ अंदाजा नहीं था कि उनका नाम क्यों बाहर किया गया। अब वे गोरखपुर जाने का अपना प्लान बना चुके थे, लेकिन वक्त उनके लिए कुछ और तय कर चुका था।

सुषमा स्वराज का फोन योगी के पास आया

चुनाव नतीजे आने थे और भाजपा पूरी तरह आश्वस्त थी कि इस बार उत्तर प्रदेश में सपाइयों को पछाड़कर वह सत्ता पर काबिज होने में सफल होगी। उधर, योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर निकलने से पहले उनके पास एक फोन आया

और यह फोन उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का था, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश योगी तक पहुंचाया था। तब भी योगी को अंदाजा नहीं था कि उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सोचा जा रहा है।

अचानक योगी के पास अमित शाह का फोन आया

11 मार्च 2017 को घोषित हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। कुल 403 सीटों में से भाजपा ने अकेले 312 सीटें जीतीं और सहयोगियों समेत कुल 325 सीटें हासिल करके ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर अनेक नाम मुख्यमंत्री पद के लिए उठने लगे थे, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम बहुत पीछे था। इधर, योगी भी गोरखपुर लौट चुके थे, तभी उन्हें अमित शाह का फोन आया, जो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली उपस्थित होने के लिए वे चार्टर्ड की व्यवस्था कर चुके थे और तय बातचीत के हिसाब से योगी भी दिल्ली पहुंच गए।

योगी ने खुद किया खुलासा

18 मार्च की सुबह योगी की मुलाकात दिल्ली में अमित शाह से उनके आवास पर हुई। यह वह मुलाकात थी, जहां अमित शाह बता चुके थे कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि, अमित शाह ने सीएम योगी से यह बात अभी गुप्त रखने के लिए बोल दिया था। उत्तराखंड में नई सरकार गठित हो रही थी, उसी बीच लखनऊ में सीएम चेहरे पर मंथन था। भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित हुआ। पूरी कहानी का खुलासा पहली बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में किया था।

गोरखनाथ मंदिर में संत समाज की बैठक

कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव नतीजों से महीनों पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की पटकथा लिख चुका था। याद हो कि मार्च 2016 में गोरखनाथ मंदिर में भारतीय संत समाज की चिंतन बैठक हुई थी। कहा जाता है कि इसी बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया था। फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिलने पर केंद्र के लिए यह फैसला लेना और भी आसान हो चुका था।

गुरु महंत अवैद्यनाथ ने दिलवाया टिकट

योगी आदित्यनाथ को सही मायने में राजनीति की राह पर गुरु महंत अवैद्यनाथ ने पहुंचाया। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में छात्रों का एक दुकानदार से झगड़ा हुआ था। यह योगी आदित्यनाथ के जीवन में एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। दुकानदार के खिलाफ छात्रों में जबरदस्त आक्रोश था और उस समय विरोध-प्रदर्शन में योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व संभालने का अवसर मिल चुका था। यहां से वे 'एंग्री यंग मैन' बन चुके थे और छात्रों के बीच मजबूत छवि बन चुकी थी। इस झगड़े के बाद सुर्खियों में आए युवा योगी आदित्यनाथ को अवैद्यनाथ ने उसी गोरखपुर लोकसभा सीट से टिकट दिलवाया, जहां से वे खुद चार बार सांसदी जीत चुके थे।

26 साल की उम्र में सांसद बने योगी

अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश और गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग पर योगी आदित्यनाथ ने साल 1998 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और महज 26 साल की उम्र में संसद के सबसे युवा सांसद बने। जनता के बीच दैनिक उपस्थिति, संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 1500 ग्राम सभाओं में प्रतिवर्ष भ्रमण व हिंदुत्व और विकास के कार्यक्रमों के कारण गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने योगी आदित्यनाथ को अपनी पहली पसंद बनाया। परिणामस्वरूप 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही विजयी रहे।

योगी आदित्यनाथ का प्रबंधन मॉडल: बीमारू राज्य से आर्थिक शक्ति बनने तक का सफर

उत्तर प्रदेश का बदलाव प्रबंधन की बड़ी कहानी है और इसीलिए आज आईआईएम के शोधार्थी 'यूपी मॉडल' पर शोधपत्र लिख रहे हैं और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है।

किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? यह एक गंभीर सवाल है और लोग इसका जवाब अपने-अपने स्तर पर अलग-अलग ही देंगे। लेकिन, संदर्भ उत्तर प्रदेश का हो तो इसका सही जवाब है-विजन। किसी भी राज्य के विकास के लिए स्पष्ट विजन का होना जरूरी है। ऐसा न हो तो संसाधन बिखरते हैं, ऊर्जा का सही उपयोग नहीं पाता और लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। 2017 में जब एक भगवादारी संन्यासी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, कारपोरेट जगत से लेकर सभी लोगों के मन में एक ही प्रश्न था कि क्या वह राज्य को विकास की राह पर ले जा पाएंगे? ऐसा राज्य जहां माफिया और अपराधियों की तूती बोलती हो, निवेशक आने से घबराते हों और जिसकी पहचान बीमारू के रूप में होती हो। लोगों के मन में यह प्रश्न उठना सहज ही था, क्योंकि प्रबंधन के स्तर पर राज्य की चूलें हिली हुई थीं। लोगों के प्रश्नों का जवाब उचित प्रबंधन ही दे सकता था और उसके बाद से अब तक का समय यदि इसकी मिसाल बना तो इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट विजन ही था।

विजन का सही एग्जिक्यूशन

कारपोरेट जगत में एक वाक्य बहुत कॉमन है- ह्यमैनेजर काम सही करता है, लीडर सही काम कराता है ह्न यह योगी आदित्यनाथ की प्रबंधकीय दृष्टि ही थी कि उन्होंने सबसे पहले सही काम तय किए और इसे सही तरीके से करने की जिद पकड़ी। मूल सिद्धांत यह कि कानून का राज ही विकास की राह है। यह उनका एक रणनीतिक घोषणापत्र था, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को एक दिशा दी, एक उद्देश्य दिया। साथ ही एक कसौटी भी रखी जिसमें हर नीति, हर निर्णय और हर अधिकारी को परखा जा सके। विजन में ऐसी स्पष्टता हो तो एग्जिक्यूशन की धार अपने आप तेज हो जाती है। बीते नौ सालों में समावेशी विकास की महागाथा, विश्वस्तरीय आयोजन और 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, यह विजन के सही एग्जिक्यूशन से ही आए। इसीलिए योगी आज एक ऐसे मैनेजमेंट गुरु के रूप में देखे जा रहे हैं, जिनके फैसले केस स्टडी के रूप में प्रबंधकीय संस्थानों और छात्रों के लिए रुचि का विषय हैं।

जीरो टॉलरेंस बना ब्रांड पोजीशनिंग टूल

योगी सरकार का लक्ष्य था कि बीमार पड़े राज्य को पुनर्जीवित किया जाए। कारपोरेट जगत में इस प्रक्रिया को ह्यटर्नअराउंडह्न कहते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। पुरानी जड़ें उखाड़ने से लेकर पुराने प्रशासनिक ढांचे तोड़ने थे। उन लोगों को भी बदलना था, जो वर्षों से ह्ययही होता आया हैह्न की मानसिकता में जी रहे थे। 2017 के पहले की स्थिति ऐसी ही थी, जिसमें पूरा तंत्र जड़ हो चुका था। न कोई जवाबदेही थी और न ही कोई संस्कृति। उत्तर प्रदेश की पहचान ह्यदंगा प्रदेशह्न के रूप में थी और यह केवल एक छवि नहीं थी, यह अभिशाप था जो युवाओं को पलायन के लिए बाध्य कर रहा था तो उद्यमियों को आने से रोक रहा था। ऐसे में राज्य की अलग पहचान तभी हो सकती थी जब पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर राज्य को ब्रांड बनाया जाए।

इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने ह्यजीरो टॉलरेंसह्न नीति को एक ह्यब्रांड पोजीशनिंग टूलह्न के रूप में इस्तेमाल किया। बुलडोजर ने अपराधियों के हौसले तोड़े तो माफिया के खिलाफ अभियान ने सीधा संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। पूरी कठोरता से इस फैसले के क्रियान्वयन ने देश के उद्योग जगत को स्पष्ट ह्यमार्केटिंग सिग्नलह्न दिया कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। परिणाम राजस्व की बड़ी उछाल के रूप में सामने आया और आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है तो यह यहां के प्रबंधन मॉडल की सफलता का परिणाम है।

कुशल सीईओ जैसी कार्यशैली

प्रबंधन में विजन और ब्रांडिंग से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है- एग्जिक्यूशन। व्यक्तिगत निगरानी और समय-सीमा के प्रति अटल प्रतिबद्धता। हर परियोजना की डेली मॉनीटरिंग, डैशबोर्ड रिव्यू और स्वयं मुख्यमंत्री की देर रात तक चलने वाली समीक्षा बैठकें, यह किसी स्टार्टअप के कुशल व मेहनती ह्यसीईओह्न की कार्यशैली नजर आती है। जब सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति खुद जवाबदेह हो, तो पूरा सिस्टम उत्तरदायी हो जाता है। 2025 का महाकुंभ इस एग्जिक्यूशन की क्षमता का सबसे बड़ा और सबसे दृश्यमान प्रमाण था। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का एक स्थान पर आना, मानव इतिहास का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और भीड़ प्रबंधन का प्रयोग था। परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, डिजिटल सेवाएं, हर विभाग को एक साथ-एक लय में चलाना, यह तब ही संभव है जब ह्यसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोलह्न व्यवहार में जीवित हो। महाकुंभ की सफलता ने प्रबंधन का ऐसा इतिहास लिखा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी दौड़े चले आए।

ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी

एक और पहलू है जिसे अनदेखा करना असंभव है- ह्यब्लू ओशन स्ट्रेटेजी।ह्न इस स्ट्रेटजी में आप प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर एक नया और अछूता बाजार बनाते हैं, जहां कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। जब सभी राज्य एक ही तरह की नीतियां अपना रहे थे, उत्तर प्रदेश ने ह्यवन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्टह्न (ओडीओपी) और बाद में ह्यवन डिस्ट्रिक्ट, वन कुजीनह्न (ओडीओसी) जैसे नवाचार किए। ओडीओपी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा आधार बन गया। इस नीति ने लाखों कारीगरों को न केवल आजीविका दी, बल्कि उन्हें एक पहचान भी दी और यही किसी भी सफल संगठन की ह्यएचआर पॉलिसीह्न का सार होता है।

शोध का विषय बना यूपी मॉडल

किसी भी गंभीर संकट में प्रबंधन की असली परीक्षा होती है। उत्तर प्रदेश ने कोविड लहर में यह परीक्षा दो बार दी। ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य ढांचे की सीमाएं और लाखों जिंदगियों की जिम्मेदारी, इन सबके बीच जो प्रशासनिक प्रतिक्रिया सामने आई, वह ह्यइंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटरह्न के रूप में थी। जिला स्तर पर निगरानी, ऑक्सीजन वितरण की रियल-टाइम ट्रैकिंग, दवाओं की उपलब्धता, यह सब उसी ह्यडैशबोर्ड गवर्नेंसह्न का विस्तार था जो इस सरकार की पहचान बन चुका है।

उत्तर प्रदेश का बदलाव प्रबंधन की बड़ी कहानी है और इसीलिए आज आईआईएम के शोधार्थी ह्ययूपी मॉडलह्न पर शोधपत्र लिख रहे हैं और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। यह किसी राज्य के लिए सामान्य बात नहीं है। भगवा कपड़ों में एक संन्यासी का सीईओ रूप सभी को प्रभावित कर रहा है। योगी ने सिद्ध किया है कि नेतृत्व की कोई पोशाक नहीं होती और न ही इसके मूल में कोई पृष्ठभूमि होती है। जनता के प्रति प्रतिबद्धता निष्कपट हो, तो मठ से निकला एक संन्यासी भी देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य का सबसे सफल ह्यटर्नअराउंड सीईओह्न बन सकता है।

'कपड़े हो गए छोटे', नसीहत देते ही हुई ट्रोल, परेशान कंटेंट क्रिएटर ने उठाया बड़ा कदम, कौन हैं अनीता बिश्नोई

(जीएनएस)।

डिजिटल दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने और लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटर्स रील्‍स और वीडियो शेयर कर पॉपुलर हो रहे हैं और उनका चेहरा इंटरनेट सेंसेशन बन जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जहां लोकप्रियता मिलती है, वहीं कंटेंट क्रिएटर/इन्फ्लुएंसर को आलोचनाओं और ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है।

ऐसा ही कुछ इंस्ट्राग्राम प्लेटफार्म की कंटेंट क्रिएटर अनीता बिश्नोई के साथ हुआ है। जिन्होंने एक वीडियो के जरिए महिलाओं के पहनावे और बदलती जीवनशैली पर चंद लाइनों के जरिए अपनी राय रखी लेकिन उन्हें नसीहत देना बहुत भारी पड़ गया। जानते हैं क्या है पूरा मामला और कौन हैं अनीता बिश्नोई?

क्या है पूरा मामला?

अनीता का "कपड़े हो गए छोटे शर्म कहां से आए..., रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहां से आए..." वीडियो

देखते ही देखते वायरल हो गया और इंटरनेट यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने अनीता की बात का समर्थन किया, जबकि कई यूजर्स ने इनकी आलोचना करते हुए जमकर ट्रोल करने लगे।

"छोटे हो गए कपड़े..." पर जमकर होने लगी आलोचना तो?

लगातार ट्रोलिंग व आलोचना से अनीता बहुत परेशान अनीता ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपनी बात रखी और उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनसे कोई शिकायत है तो सामने आकर बात करे, क्योंकि "कानून अपना काम करेगा।"

सोशल मीडिया पर अनीता इतना परेशान हो गई कि उन्होंने जहर खा लिया। पति दिनेश बिश्नोई ने बताया वो घर से बहार थे तभी उन्हें पता चला अनीता इंस्टाग्राम लाइव थीं और एक अन्य इन्फ्लुएंसर पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही थीं। तभी बेटे ने फोन कर बताया कि अनीता ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। पति ने बताया कि परिवार को लगातार धमकियां भी मिल रही थीं। उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है।

परिवार ने उन्हें तुरंत जोधपुर के एमडीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां आईसीयू में भर्ती किया गया। अस्पताल के अनुसार, वह खतरे से बाहर व स्थिर हैं, पर डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं।

कौन है अनीता बिश्नोई?

अनीता बिश्नोई राजस्‍थान के जोधपुर की रहने वाली साधारण सी शादीशुदा घरेलू महिला हैं। इनके पति का नाम दिनेश है और इनका एक बेटा भी है। अनीता सोशल मीडिया पर राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में ये नजर आती हैं। कंटेंट क्रिएटर/इन्फ्लुएंसर अनीता आमतौर पर फैशन, लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया रिलेटेड कंटेंट बनाती हैं। अनीता के सोशल मीडिया पर दस लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

'हर शहर एक जंगल है', कौन है शर्वरी वाघ ? जिसे देखकर बोले बॉबी- 'हसीना दमदार, पैसा वसूल'

(जीएनएस)।

हिंदी सिनेमा के चॉकलेटी स्टार से खतरनाक खलनायक बनकर लोगों का दिल चुराने वाले बॉबी देओल इन दिनों अपनी फिल्म 'Alpha' को लेकर लोगों के बीच सुर्खियां बने हुए हैं। फिल्म 3 जुलाई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी लेकिन इसके ट्रेलर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, इसके पीछे वजह है दो हसीनाएं जिनके एक्शन और अदाएं देखने के बाद बॉबी देओल एकदम चकित रह गए, आपने सही समझा हम यहां पर बात कर रहे हैं आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की।

आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ दोनों इस फिल्म में एक्शन करते दिखेगी, ट्रेलर में दोनों का कातिलाना अंदाज देखकर दर्शक अभी से सीटियां बजा रहे हैं। आलिया तो अक्सर अपने किरदारों से लोगों को चकित करती आई हैं लेकिन शर्वरी वाघ का धांसू अंदाज भी लोगों को पानी-पानी कर रहा है।

आपको बता दें कि बहुत कम समय में लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली शर्वरी वाघ ने अपने करियर की शुरूआत सहायक निर्देशक के तौर पर

की थी लेकिन किस्मत ने उन्हें अभिनेत्री बना दिया।

शर्वरी वाघ के नाना महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे

14 जून 1997 को एक मराठी परिवार में जन्मी शर्वरी वाघ का संबंध एक मजबूत सियासी परिवार से हैं, दरअसल उनके नाना मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शर्वरी वाघ की मम्मी का नाम नम्रता वाघ है जो कि एक आर्किटेक्ट हैं और उनके पापा का नाम शैलेश वाघ है, जो कि एक बिल्डर हैं। उन्होंने 2020 में Amazon Prime की सीरीज 'The Forgotten Army -Azaadi Ke Liye' से सनी कौशल के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरूआत की थी।

Alpha 'के साथ धमाल मचाने को तैयार Sharvari

शर्वरी ने यश राज फिल्म्स (YRF) की क्राइम कॉमेडी फिल्म 'Bunty Aur Babli 2' से फिल्मों में डेब्यू किया। इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 'Best Female Debut' का Filmfare Award और 'Star Debut of the Year - Female' का IIFA Award मिला था। इसके बाद उन्होंने 'मुंज्या बेला', 'महाराज विराज', 'वेदा वेदा', जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और इस वक्त वो 'Alpha' के साथ धमाल मचाने को तैयार हैं।

बॉबी देओल ने क्या-क्या कहा?

बॉबी देओल ने 'अल्फा' की जोरदार तारीफ करते हुए इसे एक स्टाइलिश और हाई-एनर्जी मसाला एंटरटेनर बताया है। उन्होंने कहा कि 'मैं हर दिन शूटिंग पर जाने के लिए उत्साहित रहता था क्योंकि सेट पर हमेशा कुछ न कुछ दिलचस्प और रोमांचक होता था। कलाकारों और तकनीकी टीम के बीच हर दिन आत्मीयता और गर्मजोशी महसूस होती थी, जिससे शूटिंग का माहौल बेहद ही कूल रहता था, जिसका क्रेडिट निर्देशक शिव रवैल को जाता है।' इसके बाद उन्होने आलिया और शर्वरी की तारीफ करते हुए दोनों को दमदार बताया।

'पूरी तरह से मसाला टाइम पैसा वसूल फिल्म होगी अल्फा'

उन्होंने कहा कि 'आलिया और शर्वरी को एक बड़े एक्शन स्पेक्टेकल के केंद्र में देखना भी बेहद रोमांचक था। दोनों ने अपने किरदारों के लिए जबरदस्त समर्पण और एनर्जी दिखाई, जिसने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के अनुभव को और भी खास बना दिया, दोनों कमाल हैं और दोनों का किरदार और अभिनय बेहद दमदार है, मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस फिल्म को भरपूर प्यार देंगे, ये पूरी तरह से पैसा वसूल फिल्म होगी।'

लखनऊ में किशोरियों को बेचने वाला अंतरराज्यीय गिरोह गिरफ्तार, मोहनलालगंज पुलिस ने की कार्रवाई

(जीएनएस)।

मोहनलालगंज। मोहनलालगंज पुलिस ने मासूम बच्चियों को विवाह के लिए बेचने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के तीन आरोपियों सहित एक बालअपचारी को गिरफ्तार किया गया है इस गैंग ने बीते महीने मोहनलालगंज से दो किशोरियों को अपने साथ ले जाया गया था जिसके बाद किशोरियों की नानी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों किशोरियों को बरामद कर लिया था।

मोहनलालगंज के गनियार गांव निवासी कमलेशा ने बीते 12 मई को शिकायत कर बताया था कि उनकी नातिन 16 व 12 वर्ष को उनकी रिश्तेदार अपनी साथी प्रिया पटेल निवासी रायबरेली के साथ बहला फुसलाकर ले गई इसके बाद 18 मई को पुलिस टीम ने दोनों किशोरियों को बरामद कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, विवेचना में पता चला कि एक बाल अपचारी व प्रिया पटेल निवासी रायबरेली द्वारा दोनों किशोरियों को ले गई थी। किशोरियों ने बयान में बताया कि प्रिया पटेल उनका साथी अनुराग यादव,अख्तर व बाल अपचारी द्वारा उन्हें राजस्थान ले जाया गया।

आरोपी प्रिया पटेल ने पूछताछ में बताया कि सोनम नाम की महिला से उसकी मुलाकात हुई जिसके माध्यम से किशोरियों को शादी के लिए बेचा जाता था एक लड़की पर एक से डेढ़ लाख रुपए मिलते थे। वह किशोरियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती थी और उन्हें अच्छे कपड़े दिए जाते थे इसके बाद राजस्थान ले जाकर बेच दिया था। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि रायबरेली की दो बहनों को भी कुछ समय पहले बेचा जा चुका है।

सचेंडी, घाटमपुर से आने वाले ट्रक सीधा लखनऊ नहीं जाएंगे, रामादेवी से चौडगरा डायवर्ट

(जीएनएस)।

कानपुर। इटावा, भौंती, सचेंडी और घाटमपुर की ओर से आने वाले ट्रक, डंपर, कैंटर समेत अन्य भारी वाहन रामादेवी चौराहा होकर लखनऊ नहीं जा सकेंगे। उन्हें रामादेवी हाईव से दाहिने मोड़कर वाया चौडगरा होते हुए रवाना किया जाएगा। यह डायवर्जन जाजमऊ विश्वकर्मा द्वार के पास सड़क मरम्मत के कार्य की वजह से लागू किया गया है।

ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरैया रेलवे पुल पर गर्डर रखे जाने की वजह से गंगा बैराज होकर लखनऊ जाने वाला रूट बंद है। यहां से आवाजाही करने वाले वाहनों का भार जाजमऊ रूट पर पड़ रहा है। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर जाम की स्थिति बन रही है। कानपुर और उन्नाव पुलिस की ओर से अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मी लगाए गए हैं। सचेंडी और घाटमपुर से होकर आने वाले वाहनों के डायवर्जन से कानपुर उन्नाव हाईवे पर यातायात का भार कम हो जाएगा।

जेवर एयरपोर्ट फ्लाईओवर निर्माण में कैसे हुआ भीषण हादसा? गिरी क्रेन-3 की मौत

(जीएनएस)।

नोएडा-फरीदाबाद-जेवर एक्सप्रेसवे पर गुरुवार (4 जून) दोपहर एक बड़ा निर्माण हादसा हो गया। जेवर एयरपोर्ट से जुड़े निमार्णाधीन फ्लाईओवर पर गार्डर उठाने के लिए लगाई गई भारी क्रेन अचानक पलट गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य क्रेन के नीचे दब गए।

घटना पनहेड़ा खुर्द गांव के पास हुई, जहां तेज बारिश के बाद काम शुरू किया गया था। यह हादसा न सिर्फ मजदूरों की जान ले गया, बल्कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सुरक्षा मानकों पर फिर सवाल खड़े कर गया है।

दोपहर के समय क्षेत्र में तेज बारिश हुई, जिससे निर्माण स्थल पर भारी कीचड़ और फिसलन हो गई। बारिश थमने के कुछ देर बाद मजदूर दोबारा काम पर लग गए। गार्डर (बड़ी धरातलीय बीम) उठाने का काम चल रहा था। इसी दौरान क्रेन का संतुलन बिगड़ गया और वह तेजी से पलट गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय वहां 6-7 मजदूर मौजूद थे। क्रेन के नीचे 3-4 मजदूर दब गए। आसपास काम कर रहे अन्य मजदूरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस, निर्माण कंपनी के स्टाफ और ग्रामीणों ने मिलकर मशीनों की मदद से क्रेन को हटाने और दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया गया।

यह हादसा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना का हिस्सा है। नोएडा एयरपोर्ट (जेवर) को दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर का तेजी से निर्माण चल रहा है।

फरीदाबाद से जेवर तक का यह कॉरिडोर आने वाले समय में हजारों वाहनों की आवाजाही का मुख्य मार्ग बनेगा। प्रोजेक्ट में कई फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और अंडरपास शामिल हैं। ऐसे में निर्माण की रफ्तार तेज है, लेकिन सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान न देने के आरोप भी लगते रहे हैं।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिकः

बारिश के बाद मिट्टी नरम और दलदली हो जाना

क्रेन का असंतुलित होना या ओवरलोडिंग

जमीनी स्तर पर पर्याप्त सपोर्ट न होना

तेजी में काम शुरू करना

प्रशासन और पुलिस ने हादसे के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। मजदूरों की मौत के कारणों, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और कंपनी द्वारा फॉलो किए गए प्रोटोकॉल की जांच की जाएगी। फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

बचाव कार्य और मौजूदा स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एनडीआरएफ या फायर ब्रिगेड की टीमों को भी बुलाया गया। क्रेन के भारी वजन के कारण बचाव में समय लगा। मृतकों की पहचान कर परिवारों को सूचित किया जा रहा है। घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में पहले भी छोटे-मोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन इतना गंभीर हादसा पहली बार हुआ है।

भारत में निर्माण हादसों का बढ़ता ग्राफ

यह हादसा अकेला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के दौरान कई क्रेन पलटने, स्ट्रक्चर गिरने और मजदूरों की मौत के मामले सामने आए हैं।

फिर भी ज्यादातर मामलों में बारिश के बाद बिना जांच के काम शुरू करना, पुरानी मशीनरी का इस्तेमाल और अपर्याप्त ट्रेनिंग मुख्य कारण बनते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि मॉनसून सीजन में ऐसे प्रोजेक्ट्स में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। क्रेन ऑपरेशन के लिए मौसम की जांच, सॉइल टेस्टिंग और सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए।

फरीदाबाद का यह क्रेन हादसा विकास की दौड़ में मानवीय कीमत की याद दिलाता है। जेवर एयरपोर्ट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक है, लेकिन यह विकास तभी सार्थक होगा जब निर्माण स्थलों पर हर मजदूर की जान सुरक्षित हो। प्रशासन से अपील है कि हादसे की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न दोहराए जाएं।

5 देशरत्न मार्ग अब 1 अणे मार्ग का हिस्सा नहीं बनेगा, राबड़ी विवाद के बीच सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला

(जीएनएस)।

बिहार में सरकारी बंगलों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। लालू परिवार और राज्य सरकार के बीच 10 सर्कुलर रोड वाले आवास को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास केवल 1 अणे मार्ग ही रहेगा। सरकार ने उस पुराने आदेश को भी वापस ले लिया है, जिसके तहत 5 देशरत्न मार्ग को 1 अणे मार्ग परिसर में शामिल किया गया था। इस फैसले को राबड़ी आवास विवाद के बीच अहम माना जा रहा है।

5 देशरत्न मार्ग को किया अलग

राज्य सरकार ने 5 देशरत्न मार्ग को मुख्यमंत्री आवास परिसर में शामिल करने का फैसला वापस ले लिया है। अब यह बंगला 1 अणे मार्ग से अलग ही रहेगा। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सरकार ने 2019 में पटना हाईकोर्ट में 5 देशरत्न मार्ग को उपमुख्यमंत्री का आवास बताया था। ऐसे में पुराने आदेश को वापस लेना सही कदम है।

राबड़ी देवी ने खाली करने से किया इनकार

सरकार ने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का नोटिस राबड़ी देवी को दिया है। यह बंगला अब

मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। नोटिस मिलने के बाद राबड़ी देवी ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर आवास खाली नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती है तो बलपूर्वक उन्हें हटा सकती है, लेकिन वह खुद से नहीं जाएंगी।

सम्राट चौधरी का जवाब

राबड़ी देवी के बयान पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी बंगला किसी की निजी संपत्ति नहीं होता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नियम सबके लिए समान हैं और समय आने पर वह भी मुख्यमंत्री आवास छोड़ देंगे। शेखपुरा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में वह कई सरकारी आवास बदल चुके हैं।

क्या है पूरा मामला

बिहार सरकार ने लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इससे पहले 25 नवंबर 2025 को भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बंगला खाली नहीं किया गया।फिलहाल इस आवास में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव रहते हैं।

राबड़ी को मिला नया आवास

भवन निर्माण विभाग के अनुसार, 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था। विभाग का कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें नए आवास में शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अब तक उन्होंने 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली नहीं किया है। लालू परिवार वर्ष 2005 से इस सरकारी आवास में रह रहा है।

एपीडा ने कर्नाटक से न्यूजीलैंड तक वनस्पति-युक्त बाजरे के कार्यात्मक खाद्य पदार्थों की पहली समुद्री शिपमेंट को सुगम बनाया

(जीएनएस)।

भारत के कृषि-खाद्य निर्यात को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 3 जून, 2026 को कर्नाटक से न्यूजीलैंड के लिए वनस्पति-युक्त रेडी-टू-कुक बाजरा कार्यात्मक खाद्य पदार्थों की पहली समुद्री खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने में सुविधा प्रदान की।

मूल्यवर्धित बाजरा उत्पादों से युक्त एक मीट्रिक टन की निर्यात खेप बेंगलुरु स्थित मेसर्स इंफिनी एग्रोटेक एलएलपी द्वारा भेजी गई थी। यह खेप भारत के पारंपरिक अनाजों से बने नवोन्मेषी बाजरा उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को दशार्ती है और देश से मूल्यवर्धित कृषि निर्यात के लिए बढ़ते अवसरों को रेखांकित करती है।

निर्यातकर्ता ने एपीडा द्वारा समर्थित व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों, जैसे कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, इंडस फूड 2025 और गल्फूड 2026 में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन प्रदर्शनियों में भाग लेने से कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ने, अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने और वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में मदद मिली। न्यूजीलैंड से प्राप्त निर्यात ऑर्डर एपीडा की व्यापार संवर्धन पहलों के माध्यम से सुगम बनाए गए निरंतर बाजार विस्तार और व्यावसायिक नेटवर्किंग का परिणाम है।

एपीडा के अध्यक्ष श्री अभिषेक देव, आईएएस ने वस्तुतः शिपमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस उपलब्धि पर कंपनी को बधाई देते हुए उन्होंने नवोन्मेषी बाजरा-आधारित उत्पादों के विकास और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सफल विस्तार के लिए कंपनी के प्रयासों की सराहना की।

यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बस किराए में मिलेगी छूट, सीएम योगी ने दिया आदेश

(जीएनएस)।

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 29 लाख अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रियायती किराये पर विशेष बसें चलाने, परीक्षा केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और किसी भी अभ्यर्थी को धूप में खड़ा न रहने देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं.

यूपी में सिपाही बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश में होने जा रही आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों की सुविधाओं को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं. सबसे बड़ा फैसला यह है कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए रियायती किराये पर विशेष बसों का संचालन किया जाएगा, ताकि उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था, पुलिस भर्ती परीक्षा और आगामी जनभागीदारी कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित होगी. परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में कराई जाएगी.

सबसे अहम बात यह है कि इस भर्ती परीक्षा में करीब 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है. इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां भी युद्धस्तर पर की जा रही हैं. परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन, निगरानी तंत्र और कानून-व्यवस्था को लेकर विस्तृत प्रस्तुतीकरण मुख्यमंत्री के सामने रखा गया. मुख्यमंत्री ने सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अतिरिक्त

सतर्कता बरतने के निर्देश दिए.

धूप में खड़ा नहीं रहेगा कोई अभ्यर्थी

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा निर्देश दिया, जिसकी चर्चा अब युवाओं के बीच हो रही है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी अभ्यर्थी को धूप में खड़ा रहने की नौबत नहीं आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध रहनी चाहिए. लाखों युवाओं का भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा है, इसलिए प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा देने आने वाला हर अभ्यर्थी व्यवस्था से संतुष्ट होकर वापस जाए. यही सरकार और प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

बस किराए में छूट, विशेष बसें भी चलेंगी

परीक्षा के दौरान सबसे बड़ी समस्या अक्सर यात्रा को लेकर सामने आती है. कई अभ्यर्थियों को अपने जिले से दूसरे जिले में जाकर परीक्षा देनी पड़ती है. ऐसे में परिवहन खर्च और समय दोनों बड़ी चुनौती बन जाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि अभ्यर्थियों के लिए अंतर्जनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए. साथ ही रियायती किराये की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए.

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया की लगातार निगरानी की जाए. यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाने या भ्रामक जानकारी प्रसारित करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. सरकार का उद्देश्य है कि अभ्यर्थियों के बीच किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने और परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो.

6 जून को होगा पूर्वाभ्यास

मुख्यमंत्री ने परीक्षा से पहले 6 जून को पूर्वाभ्यास कराने के निर्देश भी दिए हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या सामने न आए. सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करे. गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. यदि कहीं बिजली बाधित होती है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी पहले से तैयार रखी जाएगी. इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जाएगी. परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी और संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त निगरानी की जाएगी.

पर्यावरण अभियान को भी मिलेगी रफ्तार

बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी कार्यक्रमों की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेशभर में कम से कम 5 करोड़ पौधे लगाए जाएं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पौधों की उपलब्धता, जियो टैगिंग और संरक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल पौधारोपण कार्यक्रम नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व सम्मान का प्रतीक अभियान बनना चाहिए. मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जनआंदोलन बनाया जाना चाहिए.

12 साल पूरे होने पर जनसंवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों में शिक्षाविदों, चिकित्सकों, उद्योगपतियों, वकीलों, युवा उद्यमियों और स्टार्टअप इनोवेटर्स के साथ संवाद किया जाएगा. सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपाल लगाने के निर्देश दिए. इन चौपालों में लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और सरकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी.

उन्होंने कहा कि मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी गांवों में रात्रि प्रवास भी करें, ताकि स्थानीय समस्याओं को नजदीक से समझा जा सके. बैठक के अंत में मुख्यमंत्री का फोकस एक बार फिर भर्ती परीक्षा पर ही रहा. उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, सुरक्षा और संवेदनशीलता के साथ संपन्न कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

पीएम मोदी 1 साल के भीतर देंगे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा! राहुल गांधी का खुलासा, बोले-'मेरे पास अंदर की जानकारी'

(जीएनएस)।

देश की राजनीति में एक बार फिर से बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ऐसा दावा कर दिया है, जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता तक सबको हैरान कर दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार को चलाने और हर चीज को काबू में रखने वाला 'सिस्टम' अब पूरी तरह से टूट रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अंदरूनी हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगले एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी ने ऐसा दावा किस आधार पर किया है।

राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा सरकार के भीतर एक तरह का "संस्थागत विद्रोह" पनप रहा है और उन्हें सिस्टम के अंदर से ऐसी जानकारियां मिल रही हैं, जो संकेत देती हैं कि आने वाले समय में बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

राहुल गांधी का सनसनीखेज दावाः पीएम मोदी एक साल में छोड़ देंगे पद

बुधवार (3 जून 2026) को आयोजित 'राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव' में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल गांधी बिल्कुल अलग ही तेवर में नजर आए। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने उन्हें पारंपरिक आदिवासी टोपी भी पहनाई। मंच संभालते ही राहुल गांधी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वह देश को 'अंदर की बात' बता रहे हैं।

राहुल गांधी के मुताबिक, यह सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि व्यवस्था के अंदर से उठ रही ऐसी प्रतिक्रिया है जो आने वाले समय में बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। राहुल गांधी का अनुमान है कि मौजूदा सरकार के भीतर चल रही उथल-पुथल की वजह से पीएम मोदी एक साल के भीतर अपने पद से हट जाएंगे। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि जब भी वह संसद या किसी अन्य मौके पर प्रधानमंत्री से मिलते हैं, तो पीएम उनसे आंख से आंख मिलाकर बात तक नहीं कर पाते हैं।

▶"मेरे पास आ रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और ज्यूडिशरी के मैसेज"

राहुल गांधी ने दावा किया कि देश की बड़ी-बड़ी संवैधानिक संस्थाओं के भीतर अब 'संस्थागत विद्रोह' शुरू हो चुका है। सरकार का जो नियंत्रण पहले हुआ करता था, वह अब पूरी तरह बिखर रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि लोग सोचते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। तीन साल पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आज उनके पास खुद मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), खुफिया तंत्र के आला अधिकारियों और उच्च न्यायपालिका के लोगों के संदेश आ रहे हैं। वे सब डरे हुए हैं और व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो रहे हैं।

'इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट' से क्या मतलब है?

राहुल गांधी ने जिस शब्द 'इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट' का इस्तेमाल किया, उसका सीधा मतलब किसी हिंसक विद्रोह से नहीं है। उनके बयान के मुताबिक, इसका मतलब यह है कि सरकार जिन संस्थानों पर अपनी पकड़ मजबूत मानती है, वहां अब असहमति और नाराजगी बढ़ रही है।

हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किन संस्थानों की बात कर रहे हैं और उनके पास मौजूद "इनसाइड इंफॉर्मेशन" क्या है। इसलिए यह फिलहाल उनका राजनीतिक आकलन और दावा माना जा रहा है।

▶देश में आने वाली है सबसे बड़ी आर्थिक सुनामी और इमरजेंसी का खतरा

राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी एक बेहद डरावनी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने वाले सुरक्षा कवच को पूरी तरह हटा दिया है। इसका नतीजा यह होने वाला है कि देश में बहुत जल्द एक ऐसी भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है, जो इस देश के लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। हर जरूरी चीज के दाम आसमान छूने वाले हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने आशंका जताई कि जब इस आर्थिक संकट और महंगाई के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी, तो सरकार के हाथ से नियंत्रण पूरी तरह निकल जाएगा।